be recruited from women—50 per cent or 51 per cent?

MR. SPEAKER: Mr. Minister, will you take this suggestion?

SHRI R. VENKATARAMAN: The constitutional guarantee is that there should be no discrimination on the basis of sex. The constitutional guarantee is not that we should give employment in proportion to the population. Employment will be given on the basis of the relative merits, but there will be no disability attached to women as such for employment.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: It is true that the constitutional guarantee is against discrimination. But I feel there is so much of discrimination even in public undertakings. Even trained personnel are discriminated against. Recently in FACT, out of the Chemistry graduates who were trained there for 3 years, all the male trainees—i.e. all the trainees except the 3 women trainees—were absorbed in regular service. Only these 3 women trainees were thrown out. I approached the Minister and also requested for his intervention. But nothing has been done so far. So, there is utter disregard of women on the plea that night work is forbidden for them. When women are taken in service, the argument put forward is that men will have to do more night work. A protective legislation is passed, to protect the rights of women, because they are performing special duties in society. In order to protect the ladies, we have passed certain protective legislation; but because of that legislation, we are now losing jobs. That has come to that. What is the remedy proposed by the Government for meeting this? Everywhere we are receiving complaints viz. that in public undertakings, women are being neglected, and they are sent out of factories. This discrimination occurs even with regard to the provision of training facilities. Regarding training facilities, the ICSR was telling that because of the lack of training facilities—these various institutions are not training them—they will not be given any job. So, the training facilities are also very meager for women. What are the remedies for rectifying these training facilities handicap?

MR. SPEAKER: I shall start having prejudice now.

SHRI R. VENKATARAMAN: Night work is prohibited for women and therefore if in certain areas, they say they cannot employ women for night work, then it is not a case of prejudice; it is a case of the observance of the law of the land. It is prohibited in certain areas. (*Interruptions*) not all; you did not hear my words. "In certain areas," I said. I clearly stated that night work is prohibited in certain areas; and I said, in those cases, it is not possible, because merely by saying night work is prohibited in certain areas therefore there is a prejudice, I said, it is not so. In certain cases, it is prohibited and therefore it is not done. The other question which the hon. member asked is about training facilities. The plan of action put forward in 1977 by the Ministry of Social Welfare is that you should afford greater training facilities for women. It has not been followed in the last two or three years. We are taking it again and we are trying to implement this recommendation, namely, providing greater training facilities for women.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: They are putting forward this excuse. If such things are not brought to your notice, then what will be the remedy?

MR. SPEAKER: Next question.

Development of Tourism in Goa

*596. SHRIMATI SANYOGITA RANE: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) what measures are proposed to be taken to develop new scenic areas to attract more tourists to Goa; and

(b) money intended to be allotted for the same during the Sixth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) and (b). The Tourism plan is being reviewed with a view to gearing up facilities to meet a two-fold increase in the next five years. Among the measures contemplated to achieve this objective are:

(i) identification and development of travel circuits; and

(ii) provision of adequate infrastructural facilities at the centres falling along these travel circuits.

For this purpose discussions were held with State Tourism Officials, and details are being worked out by the Department of Tourism, Government of Goa, Daman and Diu. Their proposals are awaited.

श्रीमती संयोगिता राणे : पर्यटन विश्व का सब से बड़ा उद्योग है । इसका विकास बड़ी तेजी से हो रहा है । गत वर्ष अनुमान है कि 23 करोड़ लोग विदेशों में यात्रा पर गए । यह राजस्व प्राप्ति का सब से बड़ा साधन है । यह रोजगार का भी साधन है । पर्यटन एक प्रकार का निर्यात व्यापार है । इससे देश की अर्थ व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ता है ।

प्राकृतिक सौदर्य की दृष्टि से गोआ बहुत ही समृद्ध है । इसलिए उसे दक्षिण का नन्दनवन कहते हैं। वहा सैकड़ों ऐसे स्थल विद्यमान है जिन्हे देखने के लिए देश विदेश के कोने कोने से असख्य लोग आते है । वहा का प्राकृतिक सौदर्य बारहों महीने हरा भरा रहता है । समृद्ध समुद्र तट, पानी मे झीने, स्वास्थ्य-समृद्ध जलवायु, जाने कहा कहा से लोगो को खीच कर लाती है । ऐसा सौदर्य-समृद्ध गोआ है ।

पर्यटन की प्रथम आवश्यकता है रहने के वास्ते आरामदेह स्थान । मै जानना चाहती हूं कि भारत सरकार ने गोआ मे होटल सेवाओं मे सुधार करने, उनकी क्षमता बढ़ाने, नए होटलो की स्थापना करने, युवक होस्टल, यात्री निवास, पर्यटक काटैजिज आदि के बारे में क्या किया है, क्या कोई नई योजना बनाई है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : गोआ में अधिक संख्या में टूरिस्ट्स को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार से कई चीजो के बारे में विचार विनिमय हुआ है । पहले राज्य सरकार को सुझाव दिया गया था कि इसके इंटीग्रेटिड डिवेलेपमेंट के लिए कोई स्टेचुटरी टूरिज्म डिवेलेपमेंट आथोरिटी बनाई जाए। काफी समय तक विचार करने के बाद यह निर्णय किया कि स्टेचुटरी आथोरिटी न बना करके टूरिस्ट डिवेलेपमेंट कारपोरेशन बनाई जाए, लेकिन बाद में यह भी इन लोगों ने छोड़ दिया । अब सरकार ने टाउन एन्ड कण्ट्री प्लानिंग की गोआ दमन और दीव के लिए व्यवस्था की है । उसके अन्तर्गत इंटैग्रेटिड डिवेलपमेंट के लिए कार्य किया जा रहा है । अभी पिछले महीने हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने राज्य के टूरिस्ट विभाग के अधिकारियों से सलाह मश्विरा किया था । और उनसे कहा कि वे उन क्षेत्रों को, जहां वह डैवलप करने के लिए अधिक उचित स्थान समझते हैं, उनको बताये और उन स्थानो पर जब उनकी रिपोर्ट आ जायेगी तब विस्तार से चर्चा होगी । लेकिन मैं फिलहाल इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आई0 टी0 डी0 सी0 ने एक थ्री स्टार होटल बीच पर बनाने का निर्णय किया है, जिसके लिए 10 लाख रुपये भी सैक्शन हो चुके हैं, वैसे भी एक यूथ होस्टल बना हुआ है ।

श्रीमती संयोगिता राणे : गोआ में पर्यटन के लिए परिवहन सुविधा व अन्य रियायतें देने, विदेशों में प्रचार करने, व मनोरंजन आदि के सम्बन्ध में सरकार क्या योजनाएं बना रही है ? गोआ के जीवन और संस्कृति की झलक का प्रसार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये है ? विमान सेवा को सुधारने और हवाई अड्डे को अच्छा करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाये गये है ? वर्तमान वर्ष में इसके लिए कितना धन निर्धारित किया गया है ? छठी योजना में गोआ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : छठी योजना में जो जोड़ने की बात है, सो अभी तक इस तरह से हरेक स्टेट का निर्णय नही हुआ है, लेकिन उनके स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट से जो प्रपोजल आयेगा, उसमे यह पूछा गया है कि किन स्थानों का विकास करना चाहते है, कितना उस पर व्यय होगा और किन क्षेत्रों को वह तत्काल लाना चाहते है किन को प्राथमिकता देना चाहते है, इस सम्बन्ध मे जानकारी मागी गई है। ज्योही जानकारी आयेगी, यहा टूरिस्ट डिपार्टमेंट से विचार-विनिमय कर के यह तय किया जायेगा । जहा तक टूरिस्टो के अधिक सख्या मे वहा जाने का सवाल है, वहा गोवा का एयर-बस से जोड़ने का निर्णय लिया जा चुका है ।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Goa is admitedly one of the most important places of tourist interest in the country and yet one of the most neglected places. We do not have transport facilities. We do not have Railway facilities. We have only one on flight going to that place most of the time. There is not a single ITDC hotel up till now. Government has recently identified eight golden traingles for priority development in tourism and they are

Konarak, Puri, Bhuvneshwar, Jodhpur, Bikaner and so on. Will the hon. Minister consider including Goa also which is neglected unfortunately among these golden traingles for priority development in our national tourism policy and improve the transport facilities and the hotel facilities in that territory which are so much neglected and yet are so important from the tourists point of view?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : गोवा एक दर्शनीय स्थल है, वहां भारत के भी और विदेश के भी काफी यात्री जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां आने-जाने के साधनों की जो सुविधाएं कम है, इसीलिए गोवा को एअर-बस से जोड़ने का निर्णय लिया जा चुका है और यह काम जल्दी प्रारम्भ हो जायेगा ।

दूसरी बात यह है, माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां कोई होटल नहीं है, वहां थ्री-स्टार होटल बनाने का निर्णय आई० टी० डी० सी० द्वारा लिया जा चुका है और इसके लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था भी कर दी गई है ।

जहां तक गोल्डन ट्राइएंगिल में गोवा को जोड़ने की बात है, मुझे विश्वास है कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इस दर्शनीय स्थल के बारे में भी प्रस्ताव आयेगा और भारत सरकार का टूरिस्ट डिपार्टमेंट इस पर विचार करेगा । इस तरह जो भी सुझाव होगा उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे ।

SHRI DIGVIJAY SINH: In connection with part (b) of the question I want to ask two supplementaries. One is the very imporatnt linkage which connects northern and southern part of Goa over the Mandavi river. There is a need for a bridge across it which will develop tourism. When will that be implemented? Secondly, a meeting took place between the various officials. In that meeting, how much allocation was demanded in the Sixth Five Year Plan for development of the port and how much has been allotted?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : कितनी रकम एलाट हुई है, यह तो मुझे मालूम नहीं है । इसकी निश्चित जानकारी देने के लिए मुझे नोटिस चाहिए । गोआ में पर्यटन के विकास के लिए न केवल आई० टी० डी० सी० द्वारा होटल खोलने का निर्णय किया गया है, बल्कि वहां चार या पांच प्राईवेट होटल खोले जा रहे हैं । इसके लिए आई० एफ० सी० आई० से काफी रकम देने का निर्णय किया गया है । वहां से अभी तक प्रस्ताव नहीं आया है । गोआ के जो नागरिक विदेशों में रहते हैं, उन्होंने इस सम्बन्ध में काफ़ी दिलचस्पी ली है । हम उनकी भी सहायता करने का इरादा रखते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस सदन में अलग-अलग स्थानों को टूरिज्म के लिए डेवेलप करने के लि कई बार अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दुनिया के बहुत से देश टूरिज्म को एक इण्डस्ट्री की तरह डेवेलप कर रहे हैं और भारत एक ऐसा देश है, जिसमें बाहरी देशों से टूरिज्म की सम्भावनायें बहुत ज्यादा हैं, इस देश में भी टूरिज्म को एक इंडस्ट्री की तरह डेवेलप किया जा सकता है, बशर्ते कि सरकार पूरे देश के टूरिस्ट स्थानों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय योजना बनाये । चूंकि इस समय छठी पंच-वर्षीय योजना पर विचार हो रहा है, क्या सरकार उसमें इस बात को ध्यान में रखेग, ? मंत्री महोदय ने कहा है कि कहने के बावजूद राज्य की ओर से प्रस्ताव नही आता है । अगर राज्य सरकारों में यह कमजोरी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय पैमाने पर एक सुव्यवस्थित टूरिज्म योजना बनाई जाये और टूरिज्म को एक उद्योग की तरह विकसित किया जाये, क्या सरकार एक ऐसी टीम बनायेगी जो देश के तमाम ऐसे स्थानों को ध्यान में रख कर एक योजना तैयार करे, जहां टूरिज्म की सम्भावनायें हैं, और उसके बारे में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करे ? क्या इस योजना को बनाते समय केवल विदेशी यात्रियों का ही ध्यान नहीं रखा जायेगा, बल्कि हमारे देश के लोग भी अपने देश के दूसरे हिस्सों को देख सकें और हमारे देश का भी पर्यटन बढ़ सके, क्या इसके लिए थ्री-स्टार या फ़ाइव-स्टार होटल ही नहीं, बल्कि सस्ते टूरिस्ट लाज बनाये जायेंगे, जिनमें हमारे मध्यम वर्ग के लोग गरीब लोग, मजदूर और नौजवान रह सकें ? दूसरे देशों में इस बात को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है कि कारखानों में काम करने वाले मजदूर, नौजवान और बच्चे अपने देश के दूसरे भागों को देख सकें और इस के लिए सस्ते निवास-स्थान तथा दूसरी सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह एक अच्छा सुझाव है । जहां तक हमारे देश में टूरिज्म का सम्बन्ध है, भारतवर्ष एक बहुत ही प्राचीन देश है, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में, सब तरफ़ दर्शनीय स्थल हैं । पहले जमाने में टूरिस्ट्स के लिए धर्मशालायें और सराय बनाई जाती थीं । अब उनके स्थान पर थ्री-स्टार, फ़ोर-स्टार या फ़ाइव-स्टार होटल बनाये जा रहे हैं । अपने देश के लोगों के लिए, जो अधिक पैसा नहीं दे सकते हैं, छोटे होटल, निजी होटल और सस्ते कॉटेज बनाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अधिक से अधिक लोग अपने देश को देख सकें और हिन्दुस्तान के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी भी जा सकें । इस लिए जगह जगह टूरिस्ट सैंटर, टूरिस्ट होम और वर्कर्ज लाज बनाये जा रहे हैं । जहां तक पूरे देश

के लिए योजना बनाने का सम्बन्ध है, पूरे देश के लिए एक दस-वर्षीय योजना के बारे में विचार किया जा रहा है। 1979 में हिन्दुस्तान में 7.64 लाख यात्री आये थे। हम इस संख्या को पांच साल में—1985 तक—दुगना कर देना चाहते हैं। और इसी लिए हम टूरिस्ट स्थानों को डेवेलप करने के लिए एक टूरिस्ट पालिसी और योजना बना रहे हैं।

(d) if so, what steps the Union Government are considering to take in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATION (SHRI C. M. STEPHEN): (a) to (d). A Statement is laid on the Table of the House.

Working of Durgapur Steel Plant

*597. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Durgapur Steel Plant has been plummeting month after month;

(b) if so, whether the production in May and June has also gone to the lowest so far;

(c) if so, whether due to this many industries which are dependent on steel have suffered heavily; and

Statement

(a) and (b). It would not be correct to say that the production in Durgapur Steel Plant has been plummeting month after month or that the production in the months of May and June, 1980 has been the lowest so far. It is, however, true that the production in the plant has, in recent months, been very severely affected owing to inadequate supply of power and inadequate availability, both in terms of quality and quantity, of coking coal. The actual production of ingot steel and saleable steel during April, May and June, 1980 with reference to the targets, was as under:—

Month	Ingot steel		Saleable steel	
	Target	Actual	Target	Actual
	(All figures in tonnes)		(All figures in tonnes)	
April, 1980	89,000	57,100	70,200	31,400
May, 1980	93,000	58,700	74,200	30,200
June, 1980	82,000	55,700	72,100	45,100

(c) Except for shortfall in the production of specific items, such as wheelsets for the Railways, which are not produced by other integrated steel plants in the public sector, Durgapur Steel Plant cannot be singled out for an adverse effect on the industrial production, on account of shortage of steel items also produced by other steel plants.

(d) Captive generation of power at Durgapur Steel Plant has been maximised. It has also been decided to set up additional thermal power generation facilities consisting of 2 × 60 MW sets in the steel plant. The scheme is under implementation and the first set is likely to be commissioned in 1982-83 and the second, six months later.

Close and constant liaison is being maintained with the Ministry of Energy, Damodar Valley Corporation, Coal Supplying Agencies and the Railways to secure maximum supplies of power and good coking coal for the steel plant. Actual supplies of coal and power as well as other essential inputs are being closely monitored at various levels on a daily basis.

SHRI P. M. SAYEED: There are certain items which are exclusively